

कुडनकुलम संयंत्र की पहली इकाई में काम शुरू

परमाणु ऊर्जा नियमांक बोर्ड (एईआरबी) की मंजूरी मिल जाने के साथ ही कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र परियोजना की पहली इकाई ने काम शुरू कर दिया है। इस संयंत्र के पूरी तरह से चालू होने की दिशा में यह एक अहम कदम है।

एईआरबी के मुताबिक नियंत्रित परमाणु विखंडन प्रक्रिया की शुरुआत इसके संचालन की दिशा में पहला कदम है जिसके परिणामस्वरूप किसी रिएक्टर में विद्युत उत्पादन होता है। कुडनकुलम स्थित रूसी रिएक्टर की इकाई-1 की स्थापित क्षमता 1,000 मेगावाट है। यह संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनवेली जिले में स्थित है।

परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव आर. के सिन्हा ने बताया कि “रिएक्टर के कोर में न्यूट्रान की मात्रा में वृद्धि शुरू हो चुकी है और इसकी प्रगति काफी अच्छी है।” उन्होंने कहा कि आने वाले आठ महीनों में कुडनकुलम परियोजना की दूसरी इकाई में भी काम शुरू हो जाएगा।

इससे पहले संयंत्र के निदेशक आर. एस. सुंदर ने बताया कि अब विभिन्न चरणों में विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। पहले चरण में अगले 20-45 दिनों के भीतर 1,000 एमडब्ल्यूई संयंत्र को 400 एमडब्ल्यूई के दक्षिणी ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। विद्युत उत्पादन को धीरे धीरे 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और अंततः 100 प्रतिशत तक किया जाएगा।

इकाई में काम शुरू होने का तात्पर्य विद्युत संयंत्र में पहली बार नियंत्रित परमाणु विखंडन प्रक्रिया की शुरुआत से है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र में रूसी मूल के दो परमाणु बिजली संयंत्र होंगे जिनमें पहले चरण में प्रत्येक की क्षमता 1,000 मेगावाट की होगी। कुडनकुलम की पहली इकाई से विद्युत उत्पादन अगले दो महीने में शुरू होने की संभावना है जबकि दूसरी इकाई को अगले वर्ष के आरंभ में शुरू किया जा सकता है। एईआरबी ने सितंबर 2012 में पहली इकाई में “शुरुआती ईंधन भरने” को अंतिम मंजूरी दे दी थी। परियोजना सुरक्षा समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह और एईआरबी सलाहकार समिति द्वारा इसकी समीक्षा की गई।



एईआरबी द्वारा जारी एक वक्तव्य के मुताबिक इस समीक्षा में गुणवत्ता मानक को सुनिश्चित करने की दृष्टि से समीक्षा की गई और जांच में यह देखा गया कि “सुरक्षित संचालन के लिए अधिकृत प्रणाली में सही मानकों का अनुपालन किया गया हो।” इसे मंजूरी देते हुए इसे सुनिश्चित किया गया कि 6 मई 2013 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया हो। बिजली बंटवारे संबंधी सूत्र के मुताबिक कर्नाटक को दो विद्युत संयंत्रों से 442 मेगावाट बिजली मिलेगी।

एईआरबी ने बताया कि संयंत्र में काम शुरू करने के बारे में मंजूरी देते हुए इसे सुनिश्चित किया गया कि 6 मई को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन हो। संयंत्र की सुरक्षा लेखा संबंधी रिपोर्ट पिछले सप्ताह ही उच्चतम न्यायालय में सौंपी जा चुकी है। परियोजना की पहली इकाई के दिसंबर 2011 में ही शुरू होने की संभावना थी लेकिन उस वर्ष सितंबर में परमाणु संयंत्र के विरोध की वजह से इसमें रुकावट आई।

परमाणु संयंत्र के विरोधियों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किए गए प्रदर्शनों की वजह से आठ महीनों तक की अवधि के दौरान केवल रखरखाव संबंधी काम ही किया जा सका। वे लोग फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के मद्देनजर संयंत्र की सुरक्षा के संबंध में आशंकित थे। डॉ. आर. भट्टाचार्य ने कहा कि “इसे मंजूरी देते हुए सुरक्षा के सभी पहलुओं, इसके अधिकृत होने के परिणामों, सुधारात्मक कदमों और विभिन्न नियामक ज़रूरतों के अनुसार उसकी पूर्ति को ध्यान में रखा गया है।”

इस मंजूरी के बाद रिएक्टर के डिजाइन के अनुरूप उसके संचालन की शक्तियों के आकलन के लिए कुछ परीक्षण किए जाएंगे इसके बाद इसके अधिकृत चरण यानि रिएक्टर विद्युत स्तर में चरण वार वृद्धि की शुरुआत को मंजूरी मिलेगी।

परमाणु परियोजना भारत और रूस के बीच 1988 में हस्ताक्षरित अंतर-सरकारी समझौते का परिणाम है।

(संयंत्र के सुरक्षा पहलुओं पर अधिक जानकारी के लिए कृप्या
25-31 मई 2013 का रोजगार समाचार देखें।)